OECD MULTILINGUAL SUMMARIES

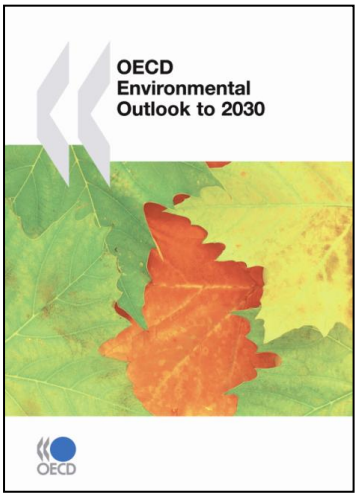

OECD Environmental Outlook to 2030

Summary in Hindi

OECD (ओईसीडी) पर्यावरणीय दृष्टिकोण 2030 के लिये

हिंदी में सारांश

- आर्थिक एवं सामाजिक विकास 2030 को पर्यावरणीय बदलाव की अगुवाई कैसे करेंगे? मुख्य पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान देने के लिये किन नीतियों की आवश्यकता होगी? इन चुनौतियों का सामना करने के लिये OECD तथा गैर OECD देश कैसे मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं?

- *OECD पर्यावरणीय दृष्टिकोण 2030 के लिये* , 2030 को आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा मुख्य चुनौतियों का सामना करने के लिये नीतिगत कार्रवाइयों का अनुकरण उपलब्ध कराता है। नई नीतियों के बिना, हमारे द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन आधार को नुकसान पहुंचाने का जोखिम बना रहेगा जबकि ये आर्थिक विकास एवं स्वस्थ मनुष्य के लिये आवश्यक है। नीतिगत कार्रवाई नहीं करने की लागत भारी है।

- लेकिन दृष्टिकोण दिखाता है कि हमारे समक्ष आज मौजूदा पर्यावरणीय समस्यों यथा - जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान, जल की कमी तथा प्रदूषण के स्वास्थ्य को नुकसान- आदि का समाधान संभव एवं वहनयोग्य है। यह नीतियों के एक ऐसे मिश्रण का उल्लेख करता है जिससे इन चुनौतियों का एक लागत प्रभावी तरीके से सामना किया जा सकता है। इस परिदृश्य के केंद्र 2001 संस्करण से विस्तारित कर OECD देशों तथा ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका (BRIICS) आदि सभी देशों में विकास परिलक्षित के लिये कर दिया गया। साथ ही इस बात पर कि वे वैश्विक एवं स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में बेहतर सहयोग कैसे कर सकते हैं।

OECD

OECD पर्यावरणीय दृष्टिकोण 2030 के लिये , वर्ष 2030 के लिये आर्थिक एवं पर्यावरणीय धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है। भविष्य के लिये प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों को "ट्रेफिक लाईट" प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किया गया है (देखें सारणी 0.1)। *दृष्टिकोण* प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिये नीतिगत कार्रवाइयों के अनुकरण को भी प्रस्तुत करता है जिनमें उनके संभावित पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव शामिल हैं।

सारणी 0.1 OECD पर्यावरणीय दृष्टिकोण 2030 के लिये

	[हरी बत्ती]	[पीली बत्ती]	[लाल बत्ती]
जलवायु परिवर्तन		• जीडीपी की प्रति इकाई के लिये GHG उत्सर्जन में कमी	• वैश्विक GHG उत्सर्जन • पहले से ही बदल रही जलवायु में बढोतरी के साक्ष्य
जैव विविधता एवं नवीकृत प्राकृतिक संसाधन	• OECD देशों में वनाच्छादित क्षेत्र	• वन प्रबंधन • संरक्षित क्षेत्र	• इकोसिस्टम गुणवत्ता • प्रजातीय नुकसान • आक्रामक विदेशी प्रजातियां • उष्णकटिबंधीय वन • अवैध जल भराव • इकोसिस्टम विखंडन
जल	• OECD देशों में प्वाइंट-स्रोत जल प्रदूषण (उद्योग, नगर निगम)	• भूतल जल गुणवत्ता एवं खराब जल शोधन	• जल कमी • भूजल गुणवत्ता • कृषि जल इस्तेमाल एवं प्रदूषण
वायु गुणवत्ता	• OECD देश SO_2 एवं NOx उत्सर्जन	• PM एवं भूस्तर ओजोन • मार्ग परिवहनउत्सर्जन	• शहरी वायु गुणवत्ता
कूडा एवं हानिकारक रसायन	• OECD देशों में जल प्रबंधन • OECD देशों में CFCs का उत्सर्जन	• नगरपालिका कचरा उत्पादन • विकासशील देशों में CFCs का उत्सर्जन	• खतरनाक कचरा प्रबंधन एवं परिवहन • विकासशील देशों में कचरा प्रबंधन • पर्यावरण,उत्पादों में रसायन

कुंजी: **हरी बत्ती** = वे पर्यावरणीय मुद्दे जिनका अच्छी तरह से प्रबंधन किया गया है, या जिनके प्रबंधन में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ हो लेकिन जिनके लिये देशों को सतर्क रहना चाहिए। **पीली बत्ती** = वे पर्यावरणीय मुद्दे जो आज भी चुनौती हैं लेकिन प्रबंधन सुधरा है, या जिनके लिये मौजूदा स्थिति अनिश्चित है, या जिनका विगत में अच्छा प्रबंधन हुआ हो लेकिन अब थोडा कम। **लाल बत्ती** = पर्यावरणीय मुद्दे जिनका अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं किया गया, जो खराब या बदतर स्थिति में हैं, और जिन पर तुरंत ध्यान दिये जाने की जरूरत है। सभी प्रवृत्तियां वैश्विक हैं जबकि उल्लेख विशेष नहीं किया गया हो।

कार्रवाई वहनीय है: नीति परिदृश्य एवं लागत

दृष्टिकोण में कुछ "लाल बत्ती" मुद्दों को रेखांकित किया गया है जिन पर तुरंत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस *दृष्टिकोण* में नीति परिदृश्य संकेत देते हैं कि चुनौतियों का सामना करने के लिये आवश्यक नीतियां एवं प्रौद्योगिकी वहनयोग्य है। पर्यावरण सुरक्षा के लिये महत्वाकांक्षी नीतिगत कार्रवाई से अर्थव्यवस्था की दक्षता में बढोतरी तथा स्वास्थ्य लागत में कमी हो सकती है। दीर्घकाल में, अधिकतर पर्यावरणीय चुनौतियों में तुरंत कारर्वाई के फायदे, लागत से कहीं अधिक होने की संभावना है।

उदाहरण के रूप में, कल्पित वैश्विक " OECD पर्यावरणीय दृष्टिकोण (EO) नीति

पैकेज" (EO नीति पैकेज, चैप्टर 20 देखें) लागू किया गया। यह दिखाता है कि कुछ विशेष नीतिगत कार्रवाइयों के जरिये, प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों में से कुछ को 2030 में वैश्विक GDP के एक प्रतिशत से थोडे से अधिक लागत में सुलझाया जा सकता है, या 2030 में औसत सालाना GDP विकास दर से लगभग 0.03 प्रतिशत अंक निम्न (आरेख 0.1)। इस तरह से 2030 में वैश्विक GDP, आज की तुलना में लगभग 97 प्रतिशत अधिक रहेगी, न कि 99 प्रतिशत अधिक। इस तरह के परिदृश्य में, 2030 में नाइट्रोजन आक्साइड तथा सल्फर आक्साइड का उत्सर्जन लगभग एक तिहाई कम रहेगा जबकि एक नई-नीति-नहीं आधारेखा परिदृश्य में मामूली बदलाव का अनुमान है और 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बढोतरी 37 प्रतिशत के बजाये 13 प्रतिशत तक सीमित हो जायेगी।

[आरेख 0.1] **2005-2030 में औसत सालाना जीडीपी विकास**

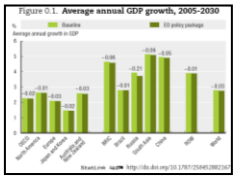

ग्रीनहाऊस गैस सांद्रता को अंतरराष्ट्रीय बातचीत (आरेख 7.5) में विचारणीय स्तर पर स्थिर करने के लिये EO नीति पैकेज की तुलना में और अधिक महत्वाकांक्षी नीतिगत कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी। इसी तरह वातावरणीय सांद्रता को 450 पीपीएम CO_2eq, पर स्थिर करने के लिये मौजूदा नीतियों का अनुकरण आवश्यक होगा, यह विचार किये जा रहे लक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुकरण दिखाते हैं कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिये, सभी देशों द्वारा कार्रवाई की जरूरत होगी ताकि 2050 तक वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में 2000 के स्तर (आरेख 0.2) की तुलना में 39 प्रतिशत कमी को हासिल किया जा सके। इस तरह की कार्रवाइयों से 2030 एवं 2050 में GDP में आधाररेखा अनुमानों से क्रमश: 0.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की जायेगी, जो सालाना GDP विकास दर में लगभग औसतन 0.1 प्रतिशत अंक प्रति वर्ष कमी के बराबर है। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण कार्रवाई में जितने अधिक देश एवं क्षेत्र शामिल होंगे, वैश्विक ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण उतना ही सस्ता एवं अधिक प्रभावी होता जायेगा। यद्यपि, इस लागत को आंकडे 0.1 में प्रदर्शित तथ्यों के अनुसार सभी क्षेत्रों में वितरित नहीं किया गया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय सहभागी ढांचे के तहत भार-हिस्सेदारी प्रणाली की आवश्यकता प्रतिपादित करता है ताकि विश्व जलवायु को संरक्षित किया जा सके। हालांकि, OECD देशों को अगुवाई करनी चाहिए, पर विशेषकर उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के विस्तृत समूह या "BRIICS" देशों (ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) के साथ और सहयोग से सामान्य पर्यावरणीय लक्ष्य कम लागत पर हासिल किये जा सकते हैं।

[आरेख 7.5] **वैश्विक GHG उत्सर्जन मार्ग: 2100 की तुलनाम में 2050 में आधाररेखा एवं न्यूनीकरण मामले स्थिरीकरण की राह**[1]

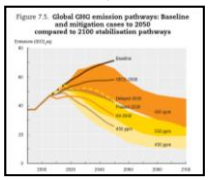

स्रोत: ओईसीडी पर्यावरणीय दृष्टिकोण आधाररेखा एवं नीति अनुकरण: एवं वेन वूरेन ए अल, 2007

[आरेख 0.2] **कुल ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन (क्षेत्रवार) 1970 2050**[2]

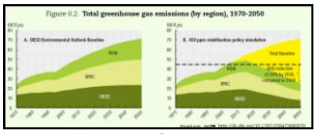

ए) *ओईसीडी पर्यावरणीय दृष्टिकोण* आधाररेखा
बी) 450 पीपीएम स्थिरीकरण नीति अनुकरण

पर्यावरणीय नीति कार्रवाई नहीं अपनाने के परिणाम

अगर कोई नई नीति कार्रवाई नहीं की जाती है, अगले कुछ ही दशकों में इस बात का खतरा होगा कि हम सतत आर्थिक समृद्धि के लिये पर्यावरणीय आधार को अनिवर्त्य रूप से पलट दें। इसे टालने के लिये, विशेषकर जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता को नुकसान, जल कमी तथा प्रदूषित एवं खतरनाक रसायनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे "लाल बत्ती" मुद्दों को सुलझाने के लिये तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। (सारणी 0.1)

2030 तक और नीति के बिना, उदाहरण के लिये:

[1] नोट: OECD 2008 = OECD देश CO_2-eq के लिये 25 अमेरिकी डालर प्रति टन का GHG कर लगायें: स्थगित 2020 = सभी देश कर को लगायें, 2020 से शुरुआत करें: चरणबद्ध 2030 = OECD देश कर को 2008 में लगाये, BRIC 2020 में तथा शेष दुनिया (ROW) 2030 में; सभी 2008 = सभी देश कर को 2008 से लगायें; 450 पीपीएम = वातावरण में GHG सांद्रण को 450 पीपीएम CO_2-eq पर स्थिर करने के लिये दृष्टिकोण; सभी 25 अमेरिकी डालर कर मामलों में, लागू करने के शुरुआती साल के बाद कर में दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढोरतरी।

[2] नोट: BRIC = ब्राजील, रूस, भारत, चीन। ROW = शेष दुनिया।

- ग्रीनहाऊस गैसों का वैश्विक उत्सर्जन और 37 प्रतिशत तथा 2050 में 52 प्रतिशत बढने का अनुमान (आरेख 0.2 ए)। इसके परिणाम में वैश्विक तापमान में 2050 तक वैश्विक तापमान में औद्योगिक-पूर्व स्तर से 1.7-2.4 डिग्री सेल्सियस के दायरे में बढोतरी हो सकती है जिससे गर्म हवाओं, सूखे, तूफान एवं बाढ आदि बढेगी और प्रमुख बुनियादी ढांचे तथा फसलों को भारी नुकसान होगा।
- आज की परिचित एवं ज्ञात पशु एवं पादप जगत की बडी संख्या में प्रजातियों के लुप्त होने की आशंका, विशेषकर बुनियादी ढांचे तथा कृषि विस्तार, साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण (आरेख 9.2)। खाद्य एवं जैव ईंधन उत्पादन के लिये कुल मिलाकर कृषि भूमि में विश्व स्तर पर 10 प्रतिशत बढोतरी की जरूरत होगी जिससे वन्य जीवों का आश्रय स्थल और सिकुडेगा। जैव विविधता को निरंतर नुकसान से पृथ्वी की मूल्यवान इकोसिस्टम सेवाएं सीमित होंगी जो कि आर्थिक विकास एवं मानव स्वास्थ्य की मददगार हैं।
- जलवायु परिवर्तन के साथ साथ संसाधनों के अस्थिर इस्तेमाल एवं प्रबंधन से जल संकट और गहरायेगा ; गंभीर जल संकट के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या एक अरब बढकर 3.9 अरब से अधिक हो सकती है। (आरेख 0.3)
- वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव बढेंगे, भूमि स्तर ओजोन से जुडी मौतों की संख्या चौगुनी (आरेख 12.2) और विविक्त सामग्री से जुडी मौतें दोगुनी हो जायेंगी। गैर OECD देशों में रसायन उत्पादन तेजी से बढ रहा है तथा पर्यावरण एवं उत्पादों में रसायनों की उपस्थिति के जोखिम के बारे में समूची जानकारी भी नहीं है।

[आरेख 9.2] मध्य प्रजाति प्रचुरता में नुकसान का स्रोत 2030 में

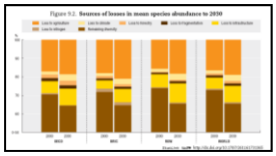

स्रोत: ओईसीडी पर्यावरणीय दृष्टिकोण आधाररेखा

[आरेख 0.3] जल दबाव के क्षेत्र में रहने वाले लोग, दबाव क स्तर से, 2005 एवं 2030

(मिलियन लोग)

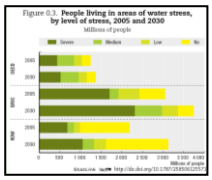

पर्यावरणीय प्रभावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों को अनुभव होगा, जो प्रबंधन और इसे अंगीकार करने के लिये कम तैयार हैं। लेकिन नीतिगत कार्रवाई में देरी या कार्रवाई के अभाव का असर इन क्षेत्रों में भारी है और इसका अर्थव्यवस्थाओं - विशेषकर OECD देशों - पर असर (प्रत्यक्ष-सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालागत के जरिये तथा अप्रत्यक्ष-श्रम उत्पादकता में कमी के रूप में) तो पहले ही पड रहा है। नीतिगत ढिलाई की लागत जैवविविधता (जैस मत्स्य पालन) तथा जलवायु परिवर्तन के लिये भारी हो सकती है।

[आरेख 12.2] शहरी ओजोन निष्कासन से असामयिक मौतें 2000 एवं 2030 के लिये

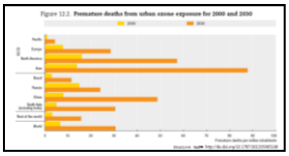

स्रोत: ओईसीडी पर्यावरणीय दृष्टिकोण आधाररेखा

मुख्य नीतिगत विकल्प

प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं से मुकाबले करने तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करने वाली महत्वाकांक्षी नीतिगत बदलाव शुरू करने के लिये अब संभावनाओं के नये द्वार हैं। मौजूदा निवेश इच्छाओं का रुख बेहतर पर्यावरणीय भविष्य की ओर मोडा जाये, विशेषकर उनकी ओर जो "ऊर्जा विधि", परिवहन बुनियादी ढांचा तथा आने वाली सदियों के लिये भंडारण में बंद रहेंगे। अग्रलिखिल कार्रवाइयां आवश्यक हैं:

- अधिकतर चुनौतियों एवं जटिल पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिये मिश्रित पूरक नीतियां अपनाई जायें, जिसके तहत बाजार-आधारित पत्रों पर विशेष जोर दिया जाये जिनमें कर तथा ट्रेड बल परमिट शामिल हैं ताकि कार्रवाई लागत कम हो।
- पर्यावरणीय ह्रास के कारण प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई की प्राथमिकता

तय की जाये: ऊर्जा, परिवहन, कृषि तथा मत्स्य पालन। पर्यावरण मंत्री इसे अकेले ही नहीं कर सकते। वित्त, अर्थ एवं कारोबार आदि सभी संबंद्ध मंत्रालयों द्वारा समूची नीति निर्धारण प्रक्रिया में पर्यावरणीय चिंताओं को जोडा जाये। साथ ही यह सभी उत्पादन एवं खपत फैसलों में परीलक्षित हो।

- सुनिश्चित है कि वैश्वीकरण से संसाधनों तथा विकास का और बेहतर इस्तेमाल तथा आर्थिक-अन्वेषण का अधिक प्रसार हो सकता है। व्यापार एवं उद्योगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी, लेकिन सरकारों को दीर्घकालिक एवं सतत् नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराना होगा ताकि आर्थिक अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जा सके तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक लक्ष्यों को सुरक्षित किया जा सके।
- वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये OECD तथा गैर OECD देशों में सहभागिता बढायें। विश्व अर्थव्यवस्था में बढती महत्ता तथा विश्व पर्यावरण दबाव में बढती भागीदारी के कारण ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका (BRIICS) आदि देश विशेषकर महत्वपूण्र सहयोगी हैं। OECD तथा गैर OECD देशों में और अधिक पर्यावरणीय सहयोग ज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठ क्रियाकलापों के प्रसार में मददगार हो सकता है।
- सीमा-पारीय एवं वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के बेहतर मुकाबले के लिये अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रशासन को मजबूत किया जाये।
- विकास सहयोग कार्यक्रमों में पर्यावरण की ओर ध्यान मजबूत किया जाये तथा और अधिक अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित किया जाये।

© OECD 2008

यह सारांश आधिकारिक OECD अनुवाद नहीं है।
इस सारांश का पुन:प्रकाशन अनुमतियोग्य है, अगर उसमें OECD कापीराईट एवं मूल प्रकाशन के शीर्षक का उल्लेख किया जाये।

मूल रूप से अंग्रेजी एवं फ्रेंच में प्रकाशितOECD प्रकाशनों के अंशों के सारांश का बहुभाषी अनुवाद किया जाता है। वे OECD की आनलाईन बुकशाप पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं-www.oecd.org/bookshop/

और अधिक जानकारी के लिये OECD राइट्स एवं अनुवाद इकाई, लोक मामले एवं संचार महानिदेशालय से यहां संपर्क करें- rights@oecd.org या फैक्स से: +33(0) 1 45 24 99 30

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

हमारी वेबसाईट पर आयें: **www.oecd.org/rights/**